

साप्ताहिक

मालव आंचल

वर्ष 47 अंक 14

(प्रति रविवार) इंदौर, 24 दिसंबर से 30 दिसंबर 2023

पृष्ठ-8

मूल्य 3 रुपये

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने नवनियुक्त मंत्रियों को दिलाई शपथ

मोहन यादव की कैबिनेट में 28 विधायकों को मिली जगह

18 मंत्री, 6 राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्यमंत्रियों ने ली शपथ

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन राजभवन के सांदीपनि सभागार में किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में 18 मंत्री, 6 राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्यमंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। मंत्री के रूप में कुंवर विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय, प्रह्लाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, उदय प्रताप सिंह, श्रीमती सम्पतिया उड्के, तुलसीराम सिलावट, एदल सिंह कंधाना, सुश्री निर्मला भूरिया, गोविन्द सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, नारायण सिंह कुशवाह, नागर सिंह चौहान, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राकेश शुक्ला, चैतन्य काश्यप 'भैया जी' और इन्द्र सिंह परमार ने शपथ ली। राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में श्रीमती कृष्णा गौर, धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल और नारायण सिंह पंवार ने शपथ ली।

राज्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में नरेन्द्र शिवाजी पटेल, श्रीमती प्रतिमा बागरी, अहिरवार दिलीप और श्रीमती राधा सिंह शामिल हैं। राजभवन में



आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा वी.डी. शर्मा एवं अन्य जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। शपथ विधि का संचालन मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा ने किया।

मोहन सरकार में घट गया सिंधिया का कद

ज्योतिरादित्य सिंधिया के उन्हीं करीबियों को मोहन यादव की कैबिनेट में जगह मिली है जो शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में मंत्री थे। 2020 के मुकाबले इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक नेताओं को मंत्रिमंडल में कम जगह मिली है। शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में 'महाराज' का दबदबा था।

सिंधिया को लगा झटका

मोहन यादव की कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा झटका लगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी और सांची विधानसभा सीट से विधायक प्रभुराम चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। प्रभुराम चौधरी को ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधव राव सिंधिया राजनीति में लेकर आए थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रभुराम चौधरी ने जीत दर्ज की है। प्रभुराम चौधरी पहले कमलनाथ की कैबिनेट फिर शिवराज चौहान की कैबिनेट में मंत्री थे।

सिंधिया समर्थक तीन नेता मंत्रिमंडल में शामिल

ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाने वाले 3 नेताओं को मोहन यादव की कैबिनेट में जगह मिली है। प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत कैबिनेट में शामिल किया गया है। वहीं, 2020 में ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले एदल सिंह कंसाना को भी मंत्री बनाया गया है। अब कंसाना को भी सिंधिया का करीबी माना जाता है।

543 लोकसभा सीटों से 5-5 हजार लोगों को अयोध्या लाने की जिम्मेदारी सांसद व विधायकों की

भाजपा 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी

लखनऊ। अयोध्या के राममंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भाजपा लोगों को अयोध्या दर्शन कराएगी। देशभर की 543 लोकसभा सीटों और सभी विधानसभा क्षेत्रों से करीब 2.5 करोड़ लोग अयोध्या जाएंगे। यहां रामलला के दर्शन और अयोध्या घूमने के बाद लोग अपने-अपने शहरों को लौटेंगे।

इस दौरान लोगों को बताया जाएगा कि कैसे भाजपा ने राममंदिर की लड़ाई लड़ी। पहले स्वरूप कैसा था, आज क्या है। इसका फायदा आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक आधारों पर क्या होने वाला है। टारगेट यह है कि हर लोकसभा सीट से 5-5 हजार लोग, जबकि हर विधानसभा क्षेत्र से 2-2 हजार लोगों को यहां लाया जाएगा। जिन राज्यों में भाजपा का कोई सांसद या विधायक नहीं है, वहां का प्रतिनिधि 2-2 हजार लोगों की व्यवस्था करेगा। करीब 3 महीने में 1 करोड़ लोगों को दर्शन-पूजन कराया जाना है। बचे 1.50 करोड़ लोगों को आने वाले महीनों में दर्शन कराया



जाएगा। सांसद-विधायक को लिस्ट तैयार कराने की जिम्मेदारी-पार्टी के सीनियर नेता ने बताया, कोर कमिटी ने तय किया है कि मौजूदा सांसद-विधायक ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करा लें। जिन्हें अयोध्या लेकर आना है। 5-5 हजार लोगों के जत्थों को 23 जनवरी के बाद रामलला के दर्शन के लिए लेकर आना है। दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को ट्रेनों के जरिए अयोध्या लाया जाएगा। लोगों को लाने, ठहरने और भोजन की पूरी व्यवस्था सांसद-विधायक अपने फंड से करेंगे। बता दें कि करीब 100 स्पेशल ट्रेन प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी के बाद अयोध्या के लिए

पूरे देश के अलग-अलग राज्यों से चलाई जा रही हैं। ये ट्रेनें 22 जनवरी के बाद 100 दिन के अंतराल में चलेंगी। लोगों तक पहुंचाएंगे अयोध्या का विकास-यहां चुनावी एजेंडा यह है कि भाजपा के मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन पदाधिकारी लोगों को बताएंगे कि 500 साल में जो नहीं हो सका, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। पॉलिटिकल माइलेज तब मिलेगा, जब यही लोग अपनी-अपनी लोकसभा क्षेत्र में लौटकर अयोध्या का डेवलपमेंट, राममंदिर और उससे जुड़े प्रयासों को लोगों तक पहुंचाएंगे।

15 जनवरी से पहले लोगों की लिस्ट होगी फाइनल-यह प्रयास यूपी ही नहीं, देश के सभी हिंदू परिवार को राम नामी धागे में पिरोने की तैयारी है। सिलेक्ट लोगों की फाइनल लिस्ट 15 जनवरी तक पूरा करना है। लोगों से संपर्क करना शुरू भी हो चुका है। वहीं, अयोध्या के प्रशासन और रामजन्म भूमि ट्रस्ट को इस बाबत जानकारी भेज दी गई है, क्योंकि इन श्रद्धालुओं के रहने और भोजन की व्यवस्था अयोध्या में ही होनी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स

यह मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के पहले लीडर



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर्स की संख्या 20 मिलियन हो गई है। आसान शब्दों में समझें तो पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ लोग जुड़े गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का यूट्यूब चैनल भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर्स के बीच यह मुकाम हासिल करने वाला पहला चैनल बन गया है। प्रधानमंत्री के चैनल में अब तक 23,403 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं, जिन वीडियो में अब तक 450 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर 6.44 मिलियन (0.64 करोड़) सब्सक्राइबर्स के साथ ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो का यूट्यूब चैनल है, जो प्रधानमंत्री मोदी से काफी पीछे है। चैनल पर शेयर किए जाते हैं प्रधानमंत्री के वीडियो-इस यूट्यूब चैनल पर प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। वह कही भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वह जुड़ते हैं तो उसे भी लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भारत सहित दुनिया में जहां भी किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं तो उसका भी लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। गुजरात बजट 2011 पर पहला वीडियो किया था अपलोड-पीएम मोदी भले ही 2007 में यूट्यूब पर आ गए थे, लेकिन उन्होंने पहला वीडियो 4 साल बाद 18 मार्च 2011 में अपलोड किया था। ये वीडियो गुजरात बजट 2011-12 का था।

संपादकीय

बहस के बिना संसद से कानून पारित होना असंवैधानिक?

संसद में इन दोनों बिना बहस के दर्जनो कानून हर सत्र में पास करा लिए जाते हैं। संसद में जब बिलों को पेश किया जाना होता है। उस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ऐसा विवाद पैदा हो जाता है। जिसके कारण हो हल्ले के बीच सरकार बिल पेश करती है, आसंदी द्वारा बहुमत के आधार पर बिलों को संसद से पास कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में जहां 140 करोड़ नागरिकों के व्यापक हितों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं सरकार बिल तैयार करने के बाद संसदीय समिति और प्रवर समिति के पास बिलों को नहीं भेजती है। कई बार तो संसद में बिल पेश किए जाते हैं। कुछ ही घंटे में बिना बहस के बिल पास भी हो जाते हैं। सांसदों को पता भी नहीं होता, कि कौन सा बिल पास हो गया। जो बिल पास हुआ है उसके क्या प्रावधान थे। सरकार जल्दबाजी में तैयार किए गए कानून संसद से पास करा लेती है। इसके बाद कानून के नियमों में बार-बार बदलाव की जरूरत महसूस होती है। जीएसटी कानून में लगभग 1700 बार से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। जो अभी तक का एक रिकॉर्ड है। जो भी कानून पिछले वर्षों में पास हो रहे हैं। उनमें अगले सत्र से ही संशोधन आना शुरू हो जाते हैं। बहुत

सारे बिल जो संसद के अधिकार क्षेत्र के होते थे। अब वह मनी बिल के रूप में पेश किये जा रहे हैं। जिसके कारण सांसदों और संसद के अधिकार भी अप्रत्यक्ष रूप से सरकार और आसंदी ने मिलकर कम कर दिए हैं। इसकी चिंता नातो सांसदों को है, ना ही चिंता आसंदी को है। आसंदी की जिम्मेदारी है, कि वह जो भी बिल सदन में पेश हो रहे हैं। उनकी व्यापक स्तर पर सचिवालय स्तर पर जांच की जाए। सदन के अंदर सभी पक्ष के सदस्यों की राय ली जाए। उसके बाद ही कानून सदन से पास होने चाहिए। कानूनो का व्यापक असर जन सामान्य पर पड़ता है। जिसमें उनके मौलिक अधिकारों से लेकर आर्थिक एवं संपत्ति के अधिकार भी शामिल होते हैं। जल्दबाजी में सरकार द्वारा बिना बहस के जो कानून सदन से पास कराकर लागू किये जा रहे हैं। उससे आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भी हो रहा है। इसके साथ सरकार की दखलेंदाजी भी नागरिकों की निजता और उनके अधिकारों पर लगातार बढ़ती जा रही है। जिसके कारण आम जनता में भी नाराजी बढ़ रही है। मुक्त अर्थव्यवस्था की आड़ में ऐसे कई कानून पास किए गए हैं। जिसका असर भारत के नागरिकों पर स्पष्ट रूप से पड़ता हुआ दिख रहा है। टेलीकॉम कंपनियों का जीडीपी में 9 फीसदी से ज्यादा का योगदान है। कई बिल मनी बिल के रूप में पेश किया जा रहे हैं। आमजनों की निजता पर प्रभाव पड़ रहा है। आर्थिक रूप से उनके ऊपर आर्थिक भार बढ़ रहा है। सामाजिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। सरकार कुछ ऐसे कानून भी संसद से पास कर रही है। जिसमें राज्यों की सहमति ली

जाना भी जरूरी है। लेकिन बिना राज्यों की सहमति लिए केंद्र सरकार कानून बनाने लगी है। धारा 370 के मामले में जम्मू कश्मीर विधानसभा की राय लिए बिना, बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं। जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में अभी इस पर निर्णय लेने का विकल्प खुला छोड़ दिया है। संसद में बैठकें बहुत कम हो रही हैं। पिछली सरकारों के समय कैग की रिपोर्ट और अन्य मामलों में विस्तृत चर्चा होती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ संसद में होता नहीं है। 2त घोटाले के समय जो राजस्व केंद्र सरकार के खजाने में उस समय में आ रहा था। उस समय इंटरनेट के कनेक्शन 1.50 करोड़ थे। जो अब बढ़कर 88.01 करोड़ हो गए हैं। लेकिन सरकार का कोई राजस्व नहीं बढ़ा। 2त समय बड़े-बड़े घोटाले के आरोप लगाए गए थे। जो प्रमाणित नहीं हुए। अब 4त के इस युग में जब सरकार की आय नहीं बढ़ रही है। तो सदन में चर्चा भी नहीं हो रही है। मनी बिल भी बिना चर्चा के पास हो रहे हैं। आम नागरिकों के ऊपर तरह-तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं। इसके बाद भी देश की आर्थिक स्थिति ठीक होने के स्थान पर और खराब हो रही है। एक सांसद द्वारा राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री करने पर जो बवाल मचा है। उससे भी बड़ा बवाल बहस के बिना जो कानून पारित किए जा रहे हैं, उन पर मचना चाहिए था। संख्या बल से कमजोर विपक्ष के होने से सारी संवैधानिक और संसदीय परंपराएं धूमिल होती जा रही है। इस स्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिए।

इंडिया गठबंधन को मिलकर मुकाबला करना होगा

ललित गर्ग

संसदीय अवरोध, विपक्षी दलों के 143 सांसदों के निलम्बन एवं उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने की घटनाओं से आक्रामक हुए राजनीतिक माहौल के बीच 28 पार्टियों का इंडिया गठबंधन विपक्षी दलों के साथ चौथी बार फिर से दिल्ली में एक छत के नीचे आया। बैठक का उद्देश्य था कि विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग एवं संयोजक के नाम पर सहमति सहित कई मुद्दों पर एक राय कायम करना। लेकिन इंडिया गठबंधन की इस बैठक में दल भले ही आपस में मिले, लेकिन दिल नहीं मिल पाये। लोकतंत्र की मजबूती के लिये सशक्त विपक्ष बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्षी दलों की संकीर्ण सोच, सिद्धान्तविहीन राजनीति एवं सत्तालालसा ने विपक्ष की राजनीति को नकारा कर दिया है। सोचा गया था कि इंडिया गठबंधन विपक्ष से जुड़ी लोकतांत्रिक भागीदारी की लौ को फिर से प्रज्वलित कर सकेगा और ऐसी सोच एवं राजनीति प्रणाली का निर्माण करेगा जो वास्तव में लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए हो। लेकिन ऐसा न होना इंडिया गठबंधन की बड़ी असफलता है और आने वाले वर्ष 2024 के लोकसभा में उसकी भूमिका टांय-टांय फिस ही होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में एकजुटता की बातें हवा हो रही हैं। न संयोजक और न ही प्रधानमंत्री और न ही नरेन्द्र मोदी के सामने कौन चुनाव लड़े के नाम पर सहमति बन पायी है।

आज दुनियाभर में लोकतंत्र विश्वास के संकट का सामना कर रहा है। भारत में विपक्ष की नकारात्मक स्थितियों के कारण यह संकट ज्यादा बढ़ा है। इसका कारण है विपक्ष से जुड़े संस्थानों, राजनीतिक हस्तियों और लोकतांत्रिक निर्णयों का आधार बनने वाली प्रणालियों पर धीरे-धीरे कम हो रहा भरोसा। विश्वास का यह संकट तत्काल कार्रवाई की मांग करता है। आज हमें विपक्षी राजनीतिक तंत्र पर मौलिक विचार मंथन के बाद पुनर्मूल्यांकन कर इन्हें पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि बदलती हुई सामाजिक एवं राष्ट्रीय जरूरतों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके और सरकार एवं शासन की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके जिसमें राजनीतिक प्रक्रियाओं का नहीं बल्कि नागरिकों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का महत्त्व हो।

इंडिया गठबंधन की प्रथम अपेक्षा है कि इससे जुड़े सभी दलों में आपसी सहमति एवं एकजुटता बने। लेकिन चौथी बैठक में ऐसा होता हुई नहीं दिखा।



सबसे खास बिहार के मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ने जल्द से जल्द सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आम सहमति बनाने की अपील की, लेकिन जिस बात का डर शुरू से था वही हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया, जिससे विपक्षी एकजुटता में सेंध लगी और राजनीतिक माहौल गरमा गया। ममता दीदी ने चाल चलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री/संयोजक पद के लिए रख दिया जबकि इस नाम के लिए नीतीश प्रारंभ से लामबंदी कर रहे थे। खड़गे का नाम सुनते ही ना सिर्फ नीतीश बल्कि नीतीश के नाम के पीछे अपने बेटे तेजस्वी का भविष्य तलाशने वाले लालू यादव भी नाराज हो गए। नाराजगी ऐसी कि दोनों दिग्गज लालू और नीतीश कुमार गठबंधन की बैठक के बीच से ही निकल गए और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि क्या गठबंधन में सिर्फ बैठकें होंगी या फिर कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा। क्या गठबंधन लोकसभा चुनाव की कोई प्रभावी एवं सार्थक चुनावी प्रक्रिया तय कर पायेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का समय बचा है। मोदी के रथ पर सवार बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन ऐड़ी चोटी का जोड़ तो लगा रही है, लेकिन सभी दल एक मुद्दे पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन कोरा सत्ता के लिए प्रयत्नशील हैं लेकिन लोकतांत्रिक आदर्श के लिए नहीं। ऐसा माना जाता है कि सत्ता समझौते पर टिकी होती है और आदर्श सिद्धांतों पर। दोनों में संतुलन और सामंजस्य की

स्थितियां दुर्लभ होती जा रही हैं। विपक्षी दल चाहे कितनी ही समझौते पैदा करते हों, लेकिन अगर वे अलग-अलग मुद्दों से ज्यादा नीतिगत प्रश्नों पर ध्यान दें तो उन्हीं के जरिए लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। कोई भी दल सत्ता में आने के लिए गठबंधन तब करता है जब अकेले सरकार बनाने या जीतने की स्थिति में नहीं होता। लेकिन आदर्शवादी राजनीति सोच इसे सत्तामोह और समझौतावादा कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि सिद्धांतवादी दलों को किसी से गठजोड़ नहीं करना चाहिए, भले उसका परिणाम राजनीतिक असफलता ही क्यों न हो। लेकिन राजनीति में गठबंधन एक विवशता बनती जा रही है, क्योंकि किसी भी विपक्षी दल में सिद्धान्त एवं मूल्यों की राजनीति करने का माद्दा नहीं उभर पा रही है।

इंडिया गठबंधन लोकतंत्र की ताकत बनना चाहिए क्योंकि इसने एकदलीय सत्ता का युग खत्म होने के बाद राजनीतिक अस्थिरता और खर्चीले चुनावों के खतरे के प्रति सचेत होकर गठबंधन की सीख बहुत जल्दी ले ली। लेकिन गठबंधन की बुनियादी सोच को विकसित किये बिना ऐसा करना जल्दबाजी एवं सत्ता मोह का निर्णय ही अधिक प्रतीत हो रहा है जिसका कोई सार्थक परिणाम आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही विपक्षी दल सिद्धांत और विचारधारा के बदले आर्थिक विकास और व्यापार-रोजगार जैसे नारों से लोगों को लुभा लें। लेकिन ऐसा करते हुए वे अवसरवाद की पुष्टि और विचारधारा के अवमूल्यन के लिए उदाहरण ही प्रस्तुत करते हैं। ऐसे दलों के नेताओं का चरित्र एवं साख भी कोई प्रभावी रंग नहीं दिखा पाती। वे एक दल से दूसरे दल में बेहिचक आते-जाते हैं, पितृदल

छोड़ कर नए-नए दल बनाते हैं। यह सब राजनीतिक विचारधारा के अंत का सूचक है। यह देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति में सिद्धांतों और मूल्यों की बातें मजाक होकर रह गई हैं। बड़ी सोच एवं बड़ी दृष्टि इन विपक्षी दलों में पनप ही नहीं पा रही है। इंडिया गठबंधन में कुछ संभावना बनी थी, लेकिन उसमें भी न तो बड़ी दृष्टि है न देश की सही समझ और न ही बड़ी लड़ाई लड़ने का दम और जीवट दिखाई पड़ता है। अगर वाकई देश को राजनीतिक विनाश के रास्ते से हटा कर सही एवं सकारात्मक रास्ते पर लाना है तो जीवट नेतृत्व की अपेक्षा है। ऐसा विपक्षी नेतृत्व उभरे जिसमें समझ और तप दोनों का समावेश हो। राष्ट्र एवं समाज को विनम्र करने का हथियार मुद्दे या लॉबी नहीं, पद या शोभा नहीं, ईमानदारी है। और यह सब प्राप्त करने के लिए ईमानदारी के साथ सौदा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि राष्ट्र, सरकार, समाज, संस्था व संविधान ईमानदारी से चलते हैं, न कि झूठे दिखावे, आश्वासन एवं वायदों से। दायित्व और उसकी ईमानदारी से निर्वाह करने की अनभिज्ञता संसार में जितनी क्रूर है, उतनी क्रूर मृत्यु भी नहीं होती। मनुष्य हर स्थिति में मनुष्य रहे। अच्छी स्थिति में मनुष्य मनुष्य रहे और बुरी स्थिति में वह मनुष्य नहीं रहे, यह मनुष्यता नहीं, परिस्थिति की गुलामी है।

हमारा विपक्षी नेतृत्व अपने पद की श्रेष्ठता और दायित्व की ईमानदारी को व्यक्तिगत अहम से ऊपर समझने की प्रवृत्ति को विकसित कर मर्यादित व्यवहार करना सीखें अन्यथा शतरंज की इस बिसात में यदि प्यादा वज्र को पीट ले तो आश्चर्य नहीं। बहुत से लोग काफी समय तक दवा के स्थान पर बीमारी ढेना पसन्द करते हैं पर क्या वे जीते जी नष्ट नहीं हो जाते? खीर को ठण्डा करके खाने की बात समझ में आती है पर बासी होने तक ठण्डा करने का क्या अर्थ रह जाता है? लोगों के दिलों को जीतने की राजनीति ही सार्थक परिणाम लाती है, विपक्षी दल यह बात भूल कर कब तक अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे। विपक्षी दलों को लोगों के विश्वास का उपभोक्ता नहीं अपितु संरक्षक बनना होगा। भारत न केवल अपने आकार के कारण, बल्कि तेजी से बदलती दुनिया में अनुकूलन और पनपने की अपनी क्षमता के कारण दुनिया की एक महाशक्ति बन रहा है, इन बदलती स्थितियों में भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती देने के लिये विपक्षी दलों को एक आदर्श मॉडल के रूप में अपनी सहभागिता देनी चाहिए।

सेंट्रल बैंक ने 113 वां स्थापना दिवस मनाया गया



इंदौर। सेंट्रल बैंक ने अपना 113 वां स्थापना दिवस मनाया। बैंक के केंद्रीय कार्यालय द्वारा योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसे ऑनलाईन सेंट्रल बैंक के सभी कार्यालयों में रिले किया गया और सभी सदस्यों ने साथ-साथ योग किया। मुख्य कार्यक्रम बैंक के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित किया गया जिसमें बैंक ने सभी उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में

ग्राहकोपयोगी 2 नए प्रोडक्ट भी लांच किए 17 फाक कि प्रगत होत इसी कड़ी में इंदौर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत एक निशुल्क सामान्य स्वास्थ्य जांच शिविर अपोलो हॉस्पिटल्स के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और ई सी जी की जांच की गई। मुख्य कार्यक्रम में इंदौर में निवासरत सेवानिवृत्त सेंट्रल बैंक कर्मियों और प्रतिष्ठित

ग्राहकों भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंदौर एलन कोचिंग संस्थान के प्रमुख के.के. शर्मा और सचिन दुबे ने सेंट्रल बैंक के साथ अपने पुराने सम्बन्धों का जिक्र करते हुए सेंट्रल बैंक की सेवाओं की प्रशंसा की। बैंक के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक अजय व्यास ने बैंक के गौरवशाली अतीत का स्मरण करते हुए बैंक के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख श्री आर के सिंह ने बताया कि 112 वर्ष पहले, देश की गुलामी के दौर में एक भारतीय द्वारा स्वदेशी बैंक की स्थापना करने का साहस करने वाले पोचखानवाला जी का यह कार्य भी एक स्वतन्त्रता संग्राम ही था, आर्थिक स्वतन्त्रता संग्राम। उन्होंने बताया कि एक छोटे से ऑफिस और छोटी केपिटल से शुरू यह प्रथम स्वदेशी बैंक आज पूरे देश के कोने-कोने में लगभग 4600 शाखाओं के साथ सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएँ दे रहा है। स्वागत भाषण सहायक महाप्रबंधक श्री निशांत रंजन ने और आगंतुकों का आभार प्रदर्शन उप क्षेत्रीय प्रमुख श्री विजय सिंह ने प्रस्तुत किया।

45 साल बाद कांग्रेस का नया पता होगा इंदिरा भवन

जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगा शिफ्ट

इंदौर। भाजपा के बाद अब कांग्रेस का भी पता बदलने वाला है। कांग्रेस जनवरी के दूसरे सप्ताह में अपने नए हेडक्वार्टर में शिफ्ट होगा। इस नए मुख्यालय का नाम इंदिरा भवन रखा गया है। बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी का दफ्तर नई दिल्ली के 24, अकबर रोड पर स्थित है। कांग्रेस का नया छह मंजिला आलीशान कार्यालय 9, कोटला रोड पर स्थित है। कांग्रेस कार्यालय वर्तमान में 24 अकबर रोड पर स्थित है, जो पिछले 45 वर्षों से कांग्रेस के उत्थान और पतन का गवाह रहा है। कांग्रेस को जनवरी 1978 में 24 अकबर रोड पर अपना नया कार्यालय मिला था। 24 अकबर रोड 10 जनपथ से जुड़ा है, जो कि कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष

सोनिया गांधी का आवास है। यह लुटियंस दिल्ली में एक टाइप 7वें बंगला है। कांग्रेस पार्टी का नया मुख्यालय छह मंजिला है। यह दीन दयाल उपाध्याय रोड स्थित है, जहां भाजपा मुख्यालय भी है। हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने इसका मुख्य द्वारा कोटला रोड पर रखा है। इस नई बिल्डिंग में कांग्रेस की सभी इकाई शिफ्ट होगी। फिलहाल, 26 अकबर रोड पर कांग्रेस का सेवा दल, 5 रायसीना रोड पर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई का कार्यालय है। इन सभी को यहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। शहरी एवं आवासीय विकास मंत्रालय ने कांग्रेस को 24 और 26 अकबर रोड सहित लुटियंस जोन में स्थित तीन कार्यालयों को खाली करने का नोटिस दिया था।

शहर में 52 केंद्रों पर शुरू हुई कोरोना की जांच

सर्दी-खांसी और बुखार के मरीजों को भीड़ में न जाने की चेतावनी

इंदौर। कोरोना के नए वेरिएंट से प्रदेश सहित इंदौर में भी हलचल मच गई है। इसके मत देना जरा स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। साथ ही सर्दी-खांसी के मरीजों को भीड़ में जाने से मना किया है। शहर में कोरोना की जांच के लिए 12 सरकारी सहित 52 केंद्र हैं, जहां कोरोना की जांच एफ़रूड है। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) की इंदौर जिला इकाई के नोडल अधिकारी डॉ. अमित मालाकार ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें नेशनल हेल्थ पोर्टल पर अपडेशन करना था कि इंदौर जिले में क्या तैयारियां हैं। इसके बाद 14 दिसंबर को एक माक ड्रिल हुई थी, जिसके बाद हमने सभी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंदौर जिले में अभी हमने 500 ऑक्सीजन बेड पता किए हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में यह बेड उपलब्ध हैं। अगर केस बढ़ते हैं तो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। शहर में अभी 48 पीएसए प्लांट में से 36 पीएसए प्लांट वर्किंग में हैं। पीएसए प्लांट की मदद से ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा

12 मेटेनेस फेस में हैं जिन्हें 2 से 3 दिन में ही शुरू किया जा सकता है। शहर में अभी ऑक्सीजन को लेकर उपलब्धता अच्छी है। टेस्ट और सैंपलिंग के लिए क्षमता बढ़ाई है। 12 केंद्रों पर हमने जांच शुरू कर दी है। शहर में कुल 52 लैब हैं जो आईसीएमआर से अफ़रूड हैं। यहां पर लोग जांच करवा सकते हैं। नया वेरिएंट कितना खतरनाक है इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी दो मरीज पाजिटिव आए थे

जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। दोनों के सैंपल भी हमने वेरिएंट की जांच के लिए भोपाल भेज दिए थे। मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है और ठंड और धूप में लगातार उतार चढ़ाव है। इस वजह से भी शहर में सर्दी, खांसी के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। सर्दी, खांसी के मरीज घर में ही रहें और स्वस्थ होने के बाद ही बाहर निकलें। वे परिजन के संपर्क में भी कम ही आए। भीड़ में जाने से बचें ताकि संक्रमण अधिक न फैले।

लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट 6 को होगा प्रकाशित

इंदौर। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोस चुनाव के लिए पहली मतदाता सूची का प्रारूप 6 जनवरी को प्रकाशित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख डॉ. अनुपम राजन ने इस संबंध में बैठक लेकर कहा कि सभी जिले लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें। मतदाता सूची में डबल इंटी एवं मृत मतदाताओं के नाम न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। जिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक है, वहां पर सहायक मतदान केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव भेजें। इसके साथ ही जहां पर मतदान भवन जर्जर हैं, उनकी जगह पर दूसरा मतदान केंद्र बनाए जाने का भी प्रस्ताव उपलब्ध कराएं। स्टैंडिंग कमेटी को भी इसकी जानकारी दें। राजन ने कहा कि 6 से 22 जनवरी तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन और नाम हटाने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। 8 फरवरी को फोटो निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।



महिलाएं अपनी शक्ति को पहचाने और अधिकारों के लिए सतत संघर्ष करें - रेणु जैन

नंदिनी लोक मित्र शिविर का समापन

इंदौर। देवी अहिल्या विश्व विद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंस विभाग तक्ष शिला परिसर में आयोजित तीन दिवसीय नंदिनी लोकमित्र शिविर का समापन हो गया। आयोजन यूनिवर्सल पीस एंड सोशल सोसाइटी और विनोबा विचार प्रवाह और गाँधी शोध पीठ ने सयुक्त रूप से किया था। अपने संबोधन में कुलपति डॉ. रेणु जैन ने कहा कि महिलाएं अपनी शक्ति को पहचाने और अपने अधिकारों के लिए सतत संघर्ष करें। गलत चीजों का खुलकर विरोध करें। गाँधी, विनोबा को हम इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा, भले ही उसके लिए उन्हें सुख वैभव छोड़ना पड़ा हो। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा के असली मायने मानवीय गुणों का विकास करना है। शिक्षा से समाज में बड़ा बदलाव आता है, अतः लड़किया अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करें और दुसरो को भी प्रेरित करें।

यह जानकारी प्रभारी प्रवीण जोशी ने दी। विनोबा विचार प्रवाह के प्रमुख रमेश भैया ने कहा कि इंदौर में तीन दिन रहकर बहुत ही आनंद आया। यह वही पावन भूमि है जहां गाँधी और विनोबा दोनों महापुरुष आये। विनोबा ने तो यहाँ भुदान के कई प्रयोग

किये, इसी वजह से यहाँ के लोगों में अधिक मैत्री, सदभाव, भाईचारा और प्रेम है। इंदौर संस्कार राजधानी है। रमेश भैया ने सभी से कहा कि एक बार वे अवश्य पवनार आश्रम में जाकर विनोबा के कार्यों को नजदीकी से देखें। विनोबा सेवा आश्रम की वरिष्ठ साधिका ज्योति पाटनकर दीदी ने कहा कि इंदौर केवल सफाई में ही नहीं, संस्कारों में भी बहुत आगे है इसका अनुभव हम सबको हुआ। यहाँ सब सहयोग करते और सदभाव रखते हैं। कोरोना काल में इंदौर ने हजारों मजदूरों की मदद की, जिसकी चर्चा आज भी होती है। संस्था अध्यक्ष डॉ. अनिल भंडारी ने कहा कि हमारी संस्था सहायता, सदाचार समिति आदि विभिन्न तरह के सेवा कार्य वर्षों से कर रही है और जिससे हजारों नागरिक लाभांविता हो रहे हैं। समाज सेवा प्रकोष्ठ और डेवलपमेंट फाउंडेशन की जानकारी श्याम पांडे ने दी।

हरिजन सेवक संघ के राष्ट्रीय-महामंत्री संजय भैया, डॉ. पुष्पेंद्र दुबे ने भी अपने विचार रखे। सभी शिवरथियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये गए। स्वागत गीत जालंध नाथ, कविता येनुकर और विमला बहिन ने गाये।

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा

लोकसभा चुनाव के हिसाब से काम करें मंत्री

भोपाल। मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्रों में एक्टिव और अलर्ट रहने को कहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से काम करने का भी निर्देश दिया है। सीएम ने कहा, विकसित भारत संपर्क यात्रा के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए भी सभी मंत्रियों को काम करना है। क्षेत्र के लोगों से अधिक से अधिक मेल-मुलाकात होनी चाहिए।



उन्होंने कहा कि जल्द ही लोकसभा क्षेत्र और जिलावार प्रभार की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी जाएगी। इस बैठक में कई मंत्रियों ने जिलों की स्थिति के हिसाब से मुख्यमंत्री को सुझाव भी दिए।

विभागों के बंटवारे पर भी हुई बातचीत-कैबिनेट बैठक में सीएम ने मंत्रियों के साथ सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में चर्चा की। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने 6 महीने के लिए कामकाज की गाइडलाइन तय की है, इस बारे में भी मंत्रियों को जानकारी दी गई। सूत्रों के मुताबिक, विभागों के बंटवारे पर भी बातचीत हुई। बैठक के बाद कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ

व्यक्तिगत मुलाकात की। यह डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की दूसरी बैठक थी। 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने दोनों डिप्टी सीएमजगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल के साथ पहली कैबिनेट मीटिंग की थी।

सामान्य प्रशासन विभाग सीएमअपने पास रखेंगे- सीएम डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट का विस्तार सोमवार को किया है। अब कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। सोमवार को 28 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। दो उप मुख्यमंत्रियों ने 13 दिसंबर को यादव के सीएमपद की शपथ लेने के साथ शपथ ग्रहण कर ली थी। अब जबकि पूरी कैबिनेट गठित हो गई है तो

सीएमविभागों के बंटवारे का काम भी पूरा करने में जुटे हैं। यह तय है कि सामान्य प्रशासन विभाग सीएमअपने पास रखेंगे और बाकी विभागों को उप मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के बीच बांटेंगे।

वीआईपीआवागमन से लोगों को तकलीफ न हो- कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में ही सभी संभागों के प्रभारी अधिकारियों की बैठक ली। कहा- कार्यों में पारदर्शिता रहे। सरकार की योजनाओं का सुदृढ़ क्रियान्वयन हो। मॉनिटरिंग की जाए। कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत रहे। मप्र में रेल सुविधाएं बढ़ाने पर अध्ययन कर सुझाव दें। सीएम ने

कहा, शहरों में यातायात प्रबंध सुगम बनाएं। वीआईपी के आवागमन से आमजन को कोई तकलीफ न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने कहा, मिलों के श्रमिकों को राहत देने का कार्य उज्जैन-इंदौर में हुआ है। जेसी मिल, ग्वालियर के मिल श्रमिक को देनदारी की राशि प्रदान करने के लिए रोडमैप बनाएं। अधिकारी प्रशासनिक कसावट पर ध्यान दें। रात्रि विश्राम कर ग्रामों की समस्याएं हल की जाएं।

भोपाल बीआरटीएस हटाने का निर्णय

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में बीआरटीएस से पैदा हुई अनेक समस्याओं के अलग-अलग पहलुओं पर विस्तार से बातचीत हुई। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर सर्वसम्मति से भोपाल के बीआरटीएस को चरणबद्ध रूप से हटाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से व्यस्त मार्गों पर यातायात का दबाव कम हो सकेगा। स्थानीय परिवहन व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। बीआरटीएस के स्थान पर सेंट्रल रोड डेवाइडर बनाया जाएगा। अब बात इंदौर की-भोपाल के बीआरटीएस को चरणबद्ध रूप से हटाने का निर्णय, भोपाल के बीआरटीएस को चरणबद्ध रूप से हटाने का निर्णय के बाद अब इंदौर के बीआरटीएस हटाने की तैयारी होगी।

असंतुलित मोहन मंत्रीमंडल, लंबा नहीं चलेगा- उमंग सिंगार



भोपाल। प्रदेश की नवनिर्वाचित मोहन सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने तंज कसा है। उनका कहना है कि मोहन सरकार में महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान नहीं दिया गया। कई वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह न दिए जाने पर भी सिंगार कटाक्ष किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के सभी साधियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपेक्षा करता हूं, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य प्रदेश के विकास में सहभागी बनेंगे।

दिग्गजों के दबाव में सीएम-उन्होंने कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना कर सभी को चौंकाया था पर मंत्रियों के नाम पर जिस तरह की कवायद की गई, उससे स्पष्ट हो गया कि पार्टी दिग्गजों के कितने दबाव में है। तीन बार मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाकर नाम जुड़वाए और कटवाए गए। इनमें कई नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री से भी सीनियर हैं, ऐसे में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के लिए उनसे तालमेल बैठाना आसान नहीं होगा।

9 महिलाओं को बनाना था मंत्री-सिंधार ने कहा कि यहां तक तो ठीक पर शपथ वाले दिन तक कई नाम बदले गए। मंत्रियों के लिए कई फार्मुले बनाए गए। पर सब कुछ धरा रह गया। प्रदेश के कई इलाके मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व से वंचित रह गए। यहां तक की आदिवासी जिले धार को भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। मोदी सरकार 33 महिलाओं को आरक्षण देने के लिए विधेयक पारित कर दिया, लेकिन मंत्रिमंडल में मात्र चार महिलाओं को सदस्य बनाया गया, जबकि 9 महिला सदस्यों को मंत्री बनाया जाना था।

ब्राह्मण समाज के लोग नाराज-सिंधार ने कहा कि सबसे अधिक मतों से जीतने वाले रमेश मेंदोला को मंत्री न बनाकर कैलाश और उनके बीच में दरार पैदा कर दी गई। नौ बार से लगातार जीतने वाले कद्दावर विधायक गोपाल भार्गव को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाने से प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हैं। इसी तरह से भूपेंद्र सिंह बृजेंद्र प्रताप सिंह और जयंत मलैया आदि कद्दावर विधायकों को मंत्रिमंडल से दूर रखा गया, जिससे मोहन सरकार असंतुलित रहेगी।

3 लाख से अधिक विद्यार्थियों को पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति

भोपाल। प्रदेश में इस वर्ष अब तक 3 लाख 30 हजार विद्यार्थियों को पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई गई है। इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में लगभग 459 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया है। पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति के अंतर्गत 32 लाख 16 हजार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 263 करोड़ की राशि का वितरण किया गया है। पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के कक्षा 11, 12 और स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गयी है। पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गयी है।

विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति-प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिये पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा रही है। इस वर्ष इस योजना का लाभ चयनित 44 विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया गया है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में करीब 7 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग के युवक-युवतियों को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने की अभिनव योजना का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। इस वर्ष कन्सट्रक्शन सेक्टर में 45 और केयर वर्कर सेक्टर में 15 चयनित युवाओं को विभाग द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है। इनमें से 5 युवाओं का रोजगार हेतु चयन जापान स्थित निजी संस्थानों में भी हो चुका है।

खेत से एग्रीकल्चर फीडर की दूरी 200 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए

मुख्यमंत्री कृषक मित्र पंप योजना में 30 हजार किसानों को मिलेगा कनेक्शन



आवेदन पर सर्वे कराया जा रहा है यह काम जनवरी और फरवरी तक पूरा हो जाएगा

भोपाल। मुख्यमंत्री कृषक मित्र पंप योजना पर प्रदेश में अमल शुरू हो चुका है। किसानों को सिंचाई पंप के लिए कनेक्शन लेने में आने वाले व्यय का आधा हिस्सा ही भुगतान करना होगा। बाकी की रकम प्रदेश सरकार और बिजली कंपनी देगी। इस योजना को लेकर किसानों में इस कदर उत्साह है कि शुरूआत में 20 हजार से ज्यादा आवेदन पहुंच गए हैं जबकि पहले साल इस योजना में महज 10 हजार किसानों को कनेक्शन दिया जाना है। फिलहाल 3300 आवेदन पर सर्वे हो चुका है। जनवरी अंत या फरवरी तक सर्वे का काम पूरा होने की उम्मीद है। जिसके बाद कृषि पंप के लिए कनेक्शन की प्रक्रिया की जाएगी।

मुख्यमंत्री कृषक मित्र पंप योजना के तहत किसानों को फीडर से खेत तक लाइन बिछाने पर लगने वाले पोल, ट्रांसफार्मर का खर्च उठाना पड़ता है। इसमें लाखों रुपये का व्यय होता है जिस वजह

से किसान परेशान होते थे। इसके पूर्व वितरण कंपनी ने मुख्यमंत्री कृषि पंप योजना चालू की थी जिसमें एक मुश्त राशि तय थी इससे ऊपर जो भी व्यय होता था कंपनी और सरकार वहन करती थी। बाद में यह योजना सरकार ने बंद कर दी थी जिसके दोबारा शुरू होने का इंतजार हो रहा था। विधानसभा चुनाव के कुछ माह पूर्व ही मुख्यमंत्री कृषक मित्र पंप योजना को लागू किया गया। इसमें खेत से एग्रीकल्चर फीडर की दूरी 200 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे उपभोक्ताओं को ही इसका लाभ मिलेगा। आवेदन बुलाए गए हैं जिनका सर्वे किया जा रहा है। यदि नियमों के तहत किसान का कनेक्शन होगा तो उसे सुविधा दी जाएगी।

50 प्रतिशत किसान को व्यय करना होगा-इस संबंध में मुख्य अभियंता परचेस पूर्व क्षेत्र कंपनी संजय भगवतकर ने बताया कि किसानों के कनेक्शन पर आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत किसान को व्यय करना होगा। शेष 40 प्रतिशत राशि सरकार और दस प्रतिशत राशि को वितरण कंपनी देगी। उन्होंने बताया कि अगले साल 20 हजार उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 20 हजार आवेदन पहुंच चुके हैं। संजय भगवतकर ने कहा कि फिलहाल आवेदन पर सर्वे कराया जा रहा है यह काम जनवरी और फरवरी तक पूरा हो जाएगा। इसके पश्चात ही कनेक्शन देने की प्रक्रिया होगी।

मुख्यमंत्री ने संभागों के प्रभारी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से की चर्चा

विकास और कानून व्यवस्था में प्रदेश बने मिसाल-मुख्यमंत्री डॉ. यादव

इंदौर, उज्जैन के बाद ग्वालियर के मिल श्रमिकों को भी मिलेगा लाभ

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि संभाग स्तर पर जनता के कल्याण और योजनाओं के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने राज्य स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों को मॉनीटरिंग का दायित्व सौंपा गया है। प्रशासनिक कसावट के साथ लोगों को सरलता से सेवाएं प्राप्त होंगी और इससे विभिन्न कठिनाइयां दूर होंगी। सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने मुख्यालय के साथ ही फील्ड में भी पर्याप्त समय दें, आवश्यकतानुसार रात्रि विश्राम कर जनता की समस्याएं समझते हुए निराकरण की प्रभावी कार्रवाई करें।



जनता को अच्छी सेवाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को मंत्रालय सभाकक्ष में एक बैठक में संभागों के प्रभारी सभी अपर मुख्य सचिवों और सभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों से चर्चा में यह बातें कही। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संभाग स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा के पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को संभागवार दायित्व सौंपे हैं। इससे अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी प्रभावी अनुश्रवण और पर्यवेक्षण का कार्य सुनिश्चित कर सकेंगे। जिलों में राज्य स्तर के विषयों का विभिन्न विभागों के समन्वय से निराकरण हो सकेगा। इस व्यवस्था में अपर मुख्य सचिव द्वारा दो माह में कम से कम एक बार संभाग के जिलों का भ्रमण कर प्रतिमाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। जिलों के लिए चिन्हित प्रमुख योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा के साथ ही मुख्यमंत्री की संभागीय बैठकों में भी अपर मुख्य सचिव उपस्थित रहेंगे। इसी तरह संभागों में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों को कानून व्यवस्था और पुलिस के कार्यों की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है।

उज्जैन की विनोद मिल और इंदौर की हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को देनदारी की राशि दी गई है। इसी तरह ग्वालियर की जेसी मिल के श्रमिकों को भी यह लाभ दिलाने के लिए रोडमैप बनाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को कहा कि ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे प्रदेश की विकास और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में मिसाल

दी जा सके। आगामी 20 - 25 वर्ष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाएं और लागू करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आमजन से प्राप्त होने वाली शिकायतों का समय पर निराकरण हो, अधिकारियों-कर्मचारियों के रात्रि विश्राम के निर्धारित शेड्यूल का भी पालन हो। नगर से ग्राम तक नागरिकों को सरलता से

सेवाएं दिलाने का कार्य होना चाहिए। जिलों में कलेक्टर और कमिश्नर के साथ वरिष्ठ अधिकारी मॉनीटरिंग करेंगे तो कार्य बेहतर होगा, यह वरिष्ठ अधिकारी सेतु की भूमिका निभाएंगे। समन्वय के साथ पारदर्शितापूर्वक शासन की योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अधिकारी आकस्मिक दौरे भी करेंगे, तो

मोहन सरकार में भी मालवा-निमाड़ 'वजनदार'

भोपाल। लंबी मशकत और कई दौर की मंत्रणाओं के बाद सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार का बहुप्रतिक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। सत्ता का गलियारा कहा जाने वाला मालवा-निमाड़ क्षेत्र मोहन सरकार में भी मजबूत ही है। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री के अलावा सात मंत्री भी इसी क्षेत्र से हैं। क्षेत्र, अनुभव, जातिगत समीकरण और नए चेहरों को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। हालांकि बीती सरकार में शामिल रहे क्षेत्र के कई वरिष्ठ विधायक इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं पा सके तो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जयवर्गीय भी बतौर कैबिनेट मंत्री सरकार में शामिल हुए हैं। विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भाजपा ने उज्जैन के विधायक डा. मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर सभी को चौंकाया था। इसके बाद इस बात के कयास राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल में भी इसी तरह चौंकाने वाले नाम नजर आएंगे। तब से लेकर केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के साथ कई दौर की चर्चाओं के बाद प्रदेश सरकार की 'नई सूरत' सामने आई है। 66 विधानसभा सीटों वाले मालवा-निमाड़ क्षेत्र से इस बार सात कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को स्थान मिला है। जबकि मंदसौर की मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से वरिष्ठ विधायक जगदीश देवड़ा को पहले ही बतौर उपमुख्यमंत्री सरकार में शामिल किया जा चुका है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर के क्षेत्र क्रमांक एक से विधायक कैलाश जयवर्गीय भी नई सरकार में बतौर मंत्री शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे विजयवर्गीय को मंत्री बनाकर संगठन ने यह संदेश भी दिया है कि भाजपा में संगठन का निर्णय ही सर्वमान्य होता है। इसके अलावा 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ

भाजपा में शामिल हुए तुलसी सिलावट भी मंत्री बने हैं। आदिवासी क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देते हुए निमाड़ के हरसूद क्षेत्र से आठ बार के विधायक विजय शाह, पांचवी बार झाबुआ जिले के पेटलावट से विधायक बनी निर्मला भूरिया और चौथी बार आलीराजपुर जिले से विधायक बने नागरसिंह चौहान को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे स्व. दिलीपसिंह भूरिया की पुत्री निर्मला दूसरी बार मंत्री बन रही हैं। इसके पूर्व वे वर्ष 2008 में भी शिवराज सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, जबकि नागरसिंह पहली बार मंत्री बन रहे हैं। क्षेत्र की 22 आदिवासी मतदाता बहुल सीटों से तीन विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। इसके अलावा रतलाम के विधायक चैतन्य काश्यप और शुजालपुर से विधायक इंदरसिंह परमार को भी मोहन सरकार में मंत्री बनाया गया है। काश्यप पहली बार मंत्री बने हैं जबकि परमार शिवराज सरकार में भी स्कूली शिक्षा मंत्री रह चुके हैं।

क्षेत्र, वरिष्ठता, जातिगत संतुलन को साधने की कोशिश-कई वरिष्ठ विधायक इस बार नहीं पा सके जगह मोहन मंत्रिमंडल में मालवा-निमाड़ क्षेत्र को पिछली सरकार की तुलना में भले ही एक मंत्री पद कम मिला है, लेकिन सरकार में मालवा-निमाड़ क्षेत्र विध्य, महाकौशल और मध्य क्षेत्र की तुलना में मजबूत है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और कैबिनेट मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विजयवर्गीय भी इंदौर से हैं। पिछली सरकार में मंत्री रहे उषा ठाकुर, ओमप्रकाश सखलेचा, हरदीपसिंह डंग को नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल सकी है। मंत्रिमंडल में मालवा-निमाड़ क्षेत्र से नए चेहरों के साथ ही अनुभवी विधायकों को शामिल कर संगठन ने संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है।



प्रभारी महासचिव के सामने फूटा गुस्सा

हम भाजपा से नहीं, कांग्रेस से ही हारे हैं चुनाव

भोपाल। मप्र कांग्रेस के प्रभारी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह के सामने कांग्रेस नेताओं का गुस्सा जमकर फूटा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस को नहीं हराया, बल्कि यह हार कांग्रेस नेताओं ने खुद असहयोग करके जुटाई है। प्रभारी के सामने ये प्रस्ताव भी रखा गया कि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने का एक ही तरीका है कि प्रत्याशियों के नाम जल्दी ऐलान कर दिए जाएं, ताकि वे अपनी तैयारी के लिए समय दे सकें।

कांग्रेस के प्रभारी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह मंगलवार को भोपाल पहुंचे। उनकी मौजूदगी में पीसीसी में हुई बैठक के दौरान बड़े नेताओं के सामने जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी का गुस्सा

फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि संगठन में नियुक्तियां हो जाती हैं, इस बारे में प्रभारी को पता नहीं होता है। उन्होंने शिकायत की कि कई जिलों में कुछ लोगों ने तानाशाही रवैया अपना रखा है। उन लोगों को लगता है कि पार्टी उनके हिसाब से चलती है। प्रभारी से कहा गया कि सबकी बात को तवज्जो दी जानी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हम भाजपा से नहीं कांग्रेस के कारण चुनाव हारे हैं। जिनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने डबल ताकत से प्रत्याशी को चुनाव हराया है। ऐसे कांग्रेसियों को चिन्हित करना चाहिए। बैठक में शामिल नेताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव के टिकट जल्दी घोषित करें और बड़े नेताओं चुनाव लड़ाया जाए।

बोनी कपूर और जान्हवी ने बेचे अपने 4 अपार्टमेंट्स



दि वंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी के जाने के बाद बोनी कपूर अपनी दोनों बेटियों का जान्हवी कपूर और खुशी कपूर और भी ज्यादा ध्यान रखने लगे हैं। दोनों बेटियां अपने पिता के बेहद करीब हैं। जान्हवी अपनी फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी हैं। उन्होंने अपनी अदाकारी से खुद के काम को साबित किया है। वहीं खुशी कपूर ने हाल ही में अपना एक्टिंग डेब्यू किया है। दोनों बहने अपनी

मां श्रीदेवी की तरह बेहतरीन अदाकारा बनना चाहती हैं। इसी बीच बोनी कपूर, जान्हवी और खुशी लगातार चर्चा में छापे हुए हैं। चर्चा में छाने के पीछे की वजह है उनके द्वारा बेचे गए चार अपार्टमेंट्स। माना जा रहा है बोनी ने अपने अंधेरी वाले 4 फ्लैट्स बेचे दिए हैं और वो भी अच्छी-खासी मोटी रकम में। एक रिपोर्ट से पता चला है कि बोनी कपूर और उनकी बेटियों ने अपना 4 अपार्टमेंट्स को बेच दिया है। ये चारों फ्लैट्स मुंबई के अंधेरी के ग्रीन एक्स

इलाके में मौजूद हैं। वहीं एक और रिपोर्ट में इन फ्लैट्स की कीमत के बारे में भी बताया गया है। जिसमें लिखा है कि सभी फ्लैट्स को 12 करोड़ से ज्यादा की कीमत में बेचा गया है। जिसमें चो फ्लैट्स की कीमत 6 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सबसे बड़ा फ्लैट 1870 वर्ग फीट क्षेत्रफल में फैला हुआ था। इस बड़े फ्लैट को अंजू नारायण और सिद्धार्थ नारायण को बेचा गया है। ●

बॉ लीवूड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों पति अभिषेक बच्चन के साथ अनबन को लेकर सुर्खियों में हैं। रूमर्स यहाँ तक उड़ रहे हैं

कि वे ससुराल छोड़कर मायके शिफ्ट हो गई हैं। वहीं इन अफवाहों के बीच हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टा पर अपने मम्मी-पापा की तस्वीरें शेयर कर दिल छू लेने वाला पोस्ट लिखा है, जिसकी इस वक्त हर तरफ चर्चा हो रही है।

दरअसल, 22 दिसंबर को ऐश्वर्या के माता-पिता वृंदा और कृष्णराज राय की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। इस खास मौके पर ऐश्वर्या ने अपने पैरेंट्स की कुछ तस्वीरें शेयर की और

ऐश्वर्या राय बच्चन ने किया माता पिता को याद



उन्हें बधाई दी है। ऐश्वर्या ने जो पहली तस्वीर शेयर की है, वो उनके मम्मी-पापा के यंग दिनों की है और दूसरी फोटो थोड़े ऑल्ड ऐज की है। इन

दोनों फोटोज को शेयर करते हुए ऐश्वर्या ने दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा है, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है। तस्वीरों को शेयर करते

हुए ऐश्वर्या ने लिखा, आपसे हमेशा प्यार करती रहूंगी, सबसे प्यारे मम्मी-डोड्डू और डैडी-अज्जा, आपकी सालगिरह पर ढेर सारी प्रार्थनाएं और प्यार, भगवान आशीर्वाद दें। बता दें कि ऐश्वर्या अपने पिता के बहुत करीब थीं। वे अक्सर उन्हें याद कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। पिता कृष्णराज भारतीय सेना में बायोलॉजिस्ट थे, उनका लंबी बीमारी से लड़ने के बाद 18 मार्च, 2017 को निधन हो गया था। ●

गर्लफ्रेंड तानिया श्राॅफ से अलग हुए अहान शेट्टी



सु नील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी अपनी लव लाइफ को लेकर हमेशा हेडलाइंस में छापे रहे हैं। वह पिछले 11 सालों से मॉडल तानिया श्राॅफ को डेट कर रहे थे। तानिया और अहान आए दिन अपनी रोमांटिक तस्वीरों से इंटरनेट का पारा बढ़ाते थे, लेकिन अब खबर है कि दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं।

तानिया से हुआ अहान शेट्टी का ब्रेकअप सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि अहान शेट्टी और तानिया श्राॅफ ने ब्रेकअप कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डेढ़ महीने पहले ही अहान और तानिया ने अपने रास्ते अलग किए हैं। दोनों अभी सिंगल हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और ना ही तानिया या अहान में से किसी ने



ब्रेकअप की आधिकारिक पुष्टि की है। तानिया श्राॅफ जयदेव और रोमिला श्राॅफ की बेटी तानिया

एक मॉडल होने के साथ डिजाइनर भी हैं। अहान और तानिया चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे। दोनों आए दिन सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ रोमांटिक फोटोज शेयर करते रहते थे। साल 2021 में अहान की फिल्म तड़प की स्क्रीनिंग के दौरान तानिया को शेट्टी परिवार के साथ भी देखा गया था।

बता दें कि कुछ दिन पहले अहान शेट्टी को अपनी बहन अथिया शेट्टी और दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए देखा गया था। हालांकि, हमेशा साथ रहने वाली तानिया, अहान संग नजर नहीं आई थीं। तभी से लोग कयास लगा रहे थे कि शायद दोनों के बीच रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। यहां तक कि दोनों पिछले कुछ समय से एक साथ तस्वीरें भी नहीं शेयर कर रहे थे। ●

खेल-कूद और एक्सरसाइज से मिलेगी कब्ज में राहत

में बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनकी दिनचर्या में कसरत को शामिल करके परेन्ट्स बाउल मूवमेंट को बेहतर रखने में मदद कर सकते हैं। वहीं आजकल के आलस से भरे लाइफस्टाइल भी इसकी एक वजह है क्योंकि बच्चे अपना अधिकतर समय स्मार्टफोन और टीवी में बिताते हैं, ऐसे में स्क्रीन टाइम को लिमिट करके उन्हें खेलने-कूदने के लिए प्रेरित करना उन्हें कब्ज जैसी समस्या से बचा सकता है। मां इस बात पर अच्छे से गौर करें कि बच्चों को कब्ज से बचाने के लिए जो तरीके अपनाए गए हैं, वे सही है या नहीं। आइये अब विस्तार से जानते हैं शारीरिक गतिविधि में क्या-क्या शामिल किया जा सकता है।



मिल जाएगा।

3. दिनचर्या बनाएं

ध्यान रहे कि जो भी एक्टिविटी आप शामिल कर रहे हों, उसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। दिनचर्या में इसे जोड़कर बच्चे को सक्रिय रखा जा सकता है।

माता-पिता को बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बनाये रखने के लिए कुछ सावधानियां और बचाव के तरीके जरूर अपनाने चाहिए। एक ऐसी हो अप्रोच जिसमें खाने-पीने में बदलाव से लेकर शारीरिक गतिविधि से जुड़ी आदतें और टॉयलेट ट्रेनिंग भी शामिल हो। इन्हीं के जरिये कब्ज की समस्या से हमेशा के लिए बचाव किया जा सकता है। ये आदतें न केवल बच्चों का पाचन बेहतर रखेंगी बल्कि उन्हें हेल्दी और खुश रखने में भी मदद करेंगी। साथ ही, अगर बच्चे की सेहत को लेकर अगर ज्यादा चिंता होने लगे तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

खराब पाचन लोगों में बढ़ती बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण है। इनमें भी पुरानी कब्ज स्वास्थ्य पर बुरा और गंभीर प्रभाव डालती है। इसके पीछे कई सारे कारक जिम्मेदार हैं जिनमें से एक खाने में फाइबर और तरल पदार्थों की कमी है।

बच्चों के खाने में फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और फलियों को अधिक से अधिक शामिल कर फाइबर की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। वहीं, पैकेट फूड और गाय के दूध का सेवन कम करने से कब्ज से राहत मिल सकती है। कुछ और जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे - बच्चे में रोजाना बाथरूम जाने की आदत बनाना और खाने से पहले एक गिलास गुनगुना पानी पीना आदि। इसी के साथ, माता-पिता को बाथरूम का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जिससे बच्चे सहज महसूस करें।

मल निकासी को आसान बनाने के लिए बच्चे को स्कॉट पोजिशन

1. लक्ष्य ऐसे हों जिन्हें पूरा किया जा सके

आसान और पूरे किये जा सकने वाले लक्ष्यों से शुरू करें और धीरे-धीरे गतिविधि का स्तर बढ़ाने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए आप छोटी सैर या आसान सी स्टेप्स से शुरूआत कर सकते हैं, फिर समय के साथ इन गतिविधियों को बढ़ाएं।

2. तरीकों को मजेदार बनायें

जिन भी एक्टिविटीज को शामिल करना हो उसे इतना मजेदार बनाएं कि बच्चा उसे करते समय खुशी और जोश दोनों महसूस करे। खेलों, गानों और दिलचस्प गतिविधियों के ढेरों आयडिया आपको इंटरनेट पर



सर्दियों में दांतों की करें देखभाल, बनेंगे मजबूत

सर्दी में शरीर को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। जरा सी लापरवाही से ठंड लगती है और जुकाम, खांसी, फ्लो होने का खतरा भी बढ़ता है। अक्सर लोग ठंड से शरीर को बचाने के लिए कई तरह की गर्म चीजों का सेवन करते हैं, जिससे सर्दी का खतरा कम हो। सर्दी होने पर शरीर के साथ दांतों को भी उचित देखभाल की आवश्यकता होती है क्योंकि सर्दी में कई बार अधिक मीठे खाने के कारण उसमें कैविटीज दांतों के अंदर दरारें और अन्य बीमारियों की संभावना बढ़ सकती है। सर्दी में दांतों में संवेदनशीलता की समस्या में भी इजाफा होता है, जो दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। सर्दी में अगर दांतों की ठीक से देखभाल न की जाए, तो दांत कमजोर होने के साथ उनमें कैविटीज की संभावना भी बढ़ती है।

हाइड्रेटेड रहें

सर्दियों में पर्याप्त पानी न पीने से दांतों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है जिससे लार का उत्पादन कम हो जाता है। लार का मुख्य कार्य दांतों से भोजन के कणों को धोना और हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ना है जो संक्रमण का कारण बनता है। दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया से बचने के लिए सर्दियों में खूब पानी पिएं।

दांत ब्रश करने का तरीका बदलें

को बनाए रखने के लिए ब्रश करना जरूरी है। खासकर सर्दियों में ब्रश करने के तरीके पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सर्दी में कम दो बार ब्रश करें। नरम ब्रिसल्स वाले टूथब्रश का उपयोग करें क्योंकि कठोर ब्रिसल्स बाहरी इनेमल परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही भोजन का सेवन करने और अपने दांतों को ब्रश करने के बीच 30 मिनट से एक घंटे का अंतर रखें।

मसूड़ों पर ध्यान दें

सर्दियों में अपने मसूड़ों की उचित देखभाल करना जरूरी होता है। बहुत से लोगों को सर्दियों में बुखार, फ्लू और सर्दी की समस्या हो जाती है। जिस कारण बैक्टीरिया मसूड़े की सूजन या पुराने मसूड़ों के संक्रमण का कारण भी बन सकते हैं। इन समस्या से राहत पाने के लिए माउथवॉश का उपयोग करें।

गर्दन के साथ-साथ अपने चेहरे को भी कवर करें

बहुत से लोग सर्दी से बचाव के लिए स्कार्फ का उपयोग करते हैं, जो चेहरे और गर्दन को गर्म रखने के साथ मसूड़ों और दांतों को भी सुरक्षित रखेगा।

सर्दियों में वजन घटाने के लिए डाइट में शामिल करें मौसमी फल



विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर चीकू के सेवन से आपको एनर्जी मिलेगी और भूख कंट्रोल में रहेगी। जिन लोगों को अक्सर मीठा खाने की क्रेविंग होती है, उनके लिए चीकू का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि चीकू का स्वाद मीठा होता है, ऐसे में इसके सेवन से आपकी मीठे की क्रेविंग शांत होगी और आप चीनी से सेवन से दूर रहेंगे।

पपीता-डॉक्टर श्रेय ने बताया कि पपीते की तासीर गर्म होती है, ऐसे में सर्दियों के मौसम में पपीते का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। पपीते में पाए जाने वाले एंजाइम और फाइबर पाचन को सहारा देने में मदद कर सकते हैं, जिससे आपका पाचन बेहतर होगा। कम कैलोरी और हाई फाइबर होने के कारण पपीता खाने के बाद आपके पेट लंबे समय तक भरा रहेगा। जिससे आप ओवर ईटिंग से बच जाएंगे। पपीते का नियमित सेवन करने से आपकी वजन कम करने की जर्नी आसान हो सकती है।

अमरूद-विटामिन ए, फाइबर और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर अमरूद सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। अमरूद में कम कैलोरी होने के साथ-साथ अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, जिससे वजन कम करना आसान हो सकता है। नियमित अमरूद का सेवन करने में मदद कर सकता है, जिससे वजन करने में मदद मिलेगी। बेहतर रिजल्ट के लिए आप नाश्ते में इन फलों का सेवन करें।

संतरा-विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर संतरे का सेवन आपकी वेट लॉस जर्नी आसान बना सकता है। इसमें मौजूद फाइबर आपको भूख को कंट्रोल में मदद कर सकता है, जिससे वजन कम करना आसान होगा। संतरे में मौजूद विटामिन ए मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और पेट संबंधी समस्याएं कम होती हैं। सर्दियों के मौसम में संतरे के सेवन से स्किन और भी बेहतर होती है।

सर्दियों के मौसम में अगर आप?

हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो सीजनल सब्जियों और फलों का सेवन जरूर करें। फलों का नियमित रूप से सेवन करने से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी और आप स्वस्थ रहेंगे।

सर्दियों में वजन घटाने के लिए खाएं

चीकू-सर्दियों के मौसम में आपको आसानी से बाजार में चीकू मिल जाएगा। कई तरह के

सर्दियों में पिएं हर्बल टी, बढ़ेगी इम्यूनिटी और बीमारियों से होगा बचाव

सर्दियों में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। इसकी वजह से व्यक्ति को तरह-तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कमजोर इम्यूनिटी की वजह से व्यक्ति को सर्दी-जुकाम और खांसी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में सर्दियों के मौसम बीमारियों से बचने के लिए आपको इम्यूनिटी को मजबूत बनाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप हर्बल टी का सेवन कर सकते हैं।

1. अदरक और हल्दी टी

सर्दियों में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप अदरक और हल्दी की हर्बल टी पी सकते हैं। अदरक और हल्दी, दोनों में पावरफुल एंटीइंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। साथ ही, अदरक और हल्दी शरीर की इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं। इसलिए सर्दियों में अदरक और हल्दी वाला हर्बल टी पीना बेहद फायदेमंद होता है। इसके लिए आप एक गिलास पानी लें। इसमें अदरक और हल्दी को कद्दकस कर लें। फिर पानी को अच्छी तरह से उबालें। इससे आपको मिलेगी।

2. दालचीनी हर्बल टी

दालचीनी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। आप सर्दियों में दालचीनी हर्बल टी पी सकते हैं। दालचीनी में कई विटामिन्स और मिनेरल्स होते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं। अगर आप सर्दियों में दालचीनी हर्बल टी पिएं, तो इससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इसके लिए आप एक गिलास



पानी में दालचीनी का टुकड़ा और इलायची डालें। फिर इसे अच्छी तरह से उबाल लें और छानकर पी लें।

3. तुलसी की चाय

आयुर्वेद में तुलसी का काफी महत्व है। तुलसी का उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। साथ ही, यह औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। इसलिए आप सर्दियों में तुलसी की चाय पी सकते हैं। इसके लिए आप एक गिलास पानी में तुलसी की पत्तियां डालें। अब इसे अच्छी तरह से उबाल लें और फिर छानकर चाय पी लें। इससे आपका तनाव दूर होगा और मूड में भी सुधार होगा।

4. मुलेठी की जड़ की चाय

आप मुलेठी की जड़ की चाय का भी सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आप मुलेठी की जड़ लें और इसे पानी में अच्छी तरह से उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए, तो छानकर पी लें। आप सर्दियों में रोजाना मुलेठी के जड़ की चाय का सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आप अच्छा महसूस करेंगे।

श्रमिकों को सम्मान और वंचितों को मान दिलाना हमारी प्राथमिकता

पीएम मोदी ने कहा कपास के क्षेत्र में इंदौर के पुराने गौरव को फिर से स्थापित करेगी डबल इंजन की सरकार

मैं मजदूर का बेटा हूँ, श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा - मुख्यमंत्री डॉ. यादव



कार्यक्रम के लिए सभी को अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे परिवारजनों आज सांकेतिक तौर पर 224 करोड़ रूपए का चेक सौंपा गया है। आने वाले दिनों में यह राशि श्रमिक भाई-बहनों तक पहुंचेगी। मैं जानता हूँ कि आपने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अब आपके सामने सुनहरे भविष्य की सुबह है। इंदौर के लोग 25 दिसम्बर की तारीख को श्रमिकों को न्याय मिलने के दिन के रूप में याद रखेंगे। मैं आपके धैर्य के आगे नतमस्तक हूँ और आपके परिश्रम को प्रणाम करता हूँ।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि देश में मेरे लिए चार जातियां सबसे बड़ी हैं। यह जातियां हैं- मेरा गरीब, मेरा युवा, मेरी माताएं-बहनें और मेरे किसान भाई-बहन। मध्यप्रदेश सरकार ने गरीबों का जीवन बदलने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गरीबों की सेवा, श्रमिकों को सम्मान और वंचितों को मान हमारी प्राथमिकता है। हमारे प्रयास हैं कि देश का श्रमिक सशक्त बनें और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छता और स्वाद के लिए मशहूर इंदौर कई क्षेत्रों में अग्रणी रहा है। इंदौर के विकास में यहां के कपड़ा उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहां के 100 साल पुराने महाराजा तुकोजीराव क्लॉथ मार्केट की ऐतिहासिकता से आप सब परिचित हैं। शहर की पहली कॉटन मिल की स्थापना होलकर राजघराने ने की थी। मालवा का कपास ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों में जाता था, और वहाँ मिलों में कपड़ा बनाया जाता था। एक समय था जब इंदौर के बाजार कपास के दाम निर्धारित करते थे। इंदौर में बने कपड़ों की माँग देश-विदेश में होती थी। यहाँ कपड़ा मिलें रोजगार का बड़ा केन्द्र बन गई थीं। इन मिलों में काम करने वाले कई श्रमिक दूसरों राज्यों से आए और यहाँ घर बसाया, यह वह दौर था जब इंदौर की तुलना मैनचेस्टर से होती थी। लेकिन समय बदला और पहले की सरकारों की नीतियों का नुकसान इंदौर को भी उठाना पड़ा।

इंदौर सहित मध्यप्रदेश के कई शहर विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन के प्रेरक उदाहरण बन रहे हैं

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार इंदौर के उस पुराने गौरव को फिर से लौटाने का भी प्रयास कर रही है। भोपाल-इंदौर के बीच इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इंदौर-पीथमपुर इकाॅनामिक कॉरिडोर एवं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का विकास हो, विक्रम उद्योगपुरी में मेडिकल ड्रिवाइस पार्क हो, धार जिले में भैसोला में



पीएम मित्र पार्क हो, सरकार द्वारा इन पर हजारों करोड़ों रूपए का निवेश किया जा रहा है। इससे यहाँ रोजगार के हजारों नए अवसर बनने की संभावना है। विकास के इन प्रोजेक्ट्स से यहाँ की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। मध्यप्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर सहित मध्यप्रदेश के कई शहर विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का प्रेरक उदाहरण बन रहे हैं। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट भी संचालित हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ ई-चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है।

जलूद प्लांट के ग्रीन बांड से पर्यावरण की रक्षा में देश के नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित होगी

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आज जलूद सोलर एनर्जी प्लांट के वर्चुअल भूमिपूजन का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इस प्लांट से प्रतिमाह 4 करोड़ रूपए के बिजली बिल की बचत होने वाली है। इस प्लांट के लिए ग्रीन बांड जारी कर लोगों से पैसा जुटाया जा रहा है। ग्रीन बांड का यह प्रयास पर्यावरण की रक्षा में देश के नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक और माध्यम बनेगा।

प्रदेशवासी मोदी की गारंटी का भरपूर लाभ उठाएं

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि चुनाव के दौरान हमने जो संकल्प लिए और जो गारंटी दी है, उसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है। हर लाभार्थी तक शासकीय योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' मध्यप्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पहुंच रही है। विधानसभा निर्वाचन के कारण मध्यप्रदेश में यह यात्रा कुछ विलंब से आरंभ हुई है, लेकिन उज्जैन से आरंभ होने के कुछ ही दिनों में इससे जुड़े 600 से भी अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं। लाखों लोगों को यात्रा से सीधा लाभ मिल रहा है। मेरा मध्यप्रदेश के सभी लोगों से आग्रह है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जब आपके यहाँ आने वाली हो, तो आप उसका भरपूर फायदा उठाएं, अधिक से अधिक लोग वहाँ पहुंचें, यह सुनिश्चित करें कि शासकीय योजनाओं के लाभ से कोई भी वंचित न रहे। मोदी की गारंटी पर भरोसा जताकर हमें प्रचंड बहुमत देने वाली मध्यप्रदेश की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको अनेक शुभकामनाएं।

श्रमिकों के संतोष के और प्रसन्नता के यह पल मुझे सदैव ऊर्जा प्रदान करेंगे - मोदी

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मुझे गरीबों और श्रमिकों से जुड़े कार्यक्रम में सहभागी होने का राज्य सरकार ने अवसर प्रदान किया। मेरे जीवन के लिए यह पल मुझे सदैव ऊर्जा प्रदान करेंगे। मैं इंदौर, मध्यप्रदेश सरकार, बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने आए श्रमिक भाई-बहनों का आभारी हूँ। लंबे संघर्ष के बाद श्रमिकों के जीवन में आज का यह शुभ अवसर आया है। श्रमिक भाईयों के संघर्ष से प्राप्त सफलता का यह संतोष और उनकी प्रसन्नता मुझे समाज के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक करने की सदैव प्रेरणा देती रहेगी।

इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता के क्षेत्र में वर्ष दर वर्ष उपलब्धियां अर्जित की हैं - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर के जनप्रतिनिधियों का अभिवादन करते हुए कहा कि इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता के क्षेत्र में वर्ष दर वर्ष उपलब्धियां अर्जित की हैं। जनप्रतिनिधियों, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के निरंतर संघर्ष से ही हुकुमचंद मिल मजदूरों की समस्या के समाधान की उपलब्धि अर्जित हुई है।

